पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10444/2012

=====

पी. सी. एम. सीमेंट कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक निजी लिमिटेड कंपनी है जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय पी. सी. एम. टावर, सेकंड माइल, सेवोक रोड, सिल्लीगुड़ी-734001, पश्चिम बंगाल में अपने संवैधानिक अटॉर्नी श्री अशोक अग्रवाल के बेटे स्वर्गीय राधेश्याम अग्रवाल, निवासी 39 ई/1, गोबिंदा अड्डी रोड, कोलकाता-700027 के माध्यम से है।

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, वैशाली के माध्यम से भारत संघ।
2. उप मुख्य अभियंता (निर्माण-I), पूर्व मध्य रेलवे, दरभंगा।
3. एफ. ए. और सी. ए. ओ., पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रघाट, पटना।
4. बिहार राज्य, वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार, पटना के माध्यम से।
5. सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, पटना उत्तर सर्कल, पटना।
6. उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, सहारसा।

..... उत्तरदातागण

=====

बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 - धारा 40 और 41

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के द्वारा अग्रिम मूल्य वर्धित कर जो कथित रूप से बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत अवैध रूप से कटौती और वसूली की गयी थी, को वापस करने का निर्देश देने की मांग की है।

खंड-पी. ने *कोन एलिवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु(2014)7 एस.सी.सी.* तथा *आंध्र प्रदेश राज्य बनाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-लिमिटेड(2002)5 एस.सी.सी. 203* पर भरोसा किया।

निर्णित किया गया कि वर्तमान मामला याचिकाकर्ता द्वार निर्मित वस्तुओं की शुद्ध और सरल बिक्री है। इसमें कोई कार्य अनुबंध शामिल नहीं है।

फिर निर्णित किया गया कि जो विवाद उठाया गया था, वह मध्यस्थता योग्य नहीं था।

याचिकाकर्ता को धनवापसी का हकदार माना गया।

रिट याचिका को स्वीकार किया गया।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10444/2012

=====

पी. सी. एम. सीमेंट कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक निजी लिमिटेड कंपनी है जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय पी. सी. एम. टावर, सेकंड माइल, सेवोक रोड, सिल्लीगुड़ी-734001, पश्चिम बंगाल में अपने संवैधानिक अटॉर्नी श्री अशोक अग्रवाल के बेटे स्वर्गीय राधेश्याम अग्रवाल, निवासी 39 ई/1, गोबिंदा अड्डी रोड, कोलकाता-700027 के माध्यम से है।

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, वैशाली के माध्यम से भारत संघ।
2. उप मुख्य अभियंता (निर्माण-I), पूर्व मध्य रेलवे, दरभंगा।
3. एफ. ए. और सी. ए. ओ., पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रघाट, पटना।
4. बिहार राज्य, वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार, पटना के माध्यम से।
5. सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, पटना उत्तर सर्कल, पटना।
6. उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, सहारसा।

..... उत्तरदातागण

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता

श्री किशोर सिंह, अधिवक्ता,

प्रतिवादीगण के लिए: श्री अंशय बहादुर माथुर, सी. जी. सी.

श्री विकास कुमार, एस. सी-11

=====

गणपूर्ति:-माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

कैव न्यायनिर्णय

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक- 28 - 07 -2023

1. रिट याचिका दायर की गई है जिसके द्वारा प्रतिवादियों 2,3 और 6 से 38, 22, 897 रु. की राशि वापस करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिकाकर्ता का तर्क है कि उक्त राशि बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षिप्त "वैट अधिनियम" के लिए) की धारा 40 और 41 के प्रावधानों के तहत कथित रूप से अग्रिम मूल्य वर्धित कर के रूप में याचिकाकर्ता के बिलों से अवैध रूप से कटौती और वसूली की गई थी।

2. याचिकाकर्ता का तर्क है कि वैट अधिनियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा रेलवे को माल का निर्माण और आपूर्ति एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी; जो बिहार राज्य के भीतर माल की बिक्री या कार्य अनुबंध के रूप में बिक्री कर के लिए अपेक्षित नहीं है।

3. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सत्यबीर भारती और प्रत्यर्थियों 1,2,3 और 6 के विद्वान वकील श्री अंशय बहादुर माथुर और राज्य के विद्वान वकील श्री विकास कुमार को सुना है।

4. याचिकाकर्ता ने पूर्व मध्य रेलवे के साथ दो अलग-अलग समझौते किए, जिनमें से पहला अनुलग्नक-2 के रूप में और दूसरा अनुलग्नक-5 के रूप में क्रमशः दिनांक 26.12.2008 और 19.05.2010 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा निविदा में सफलतापूर्वक बोली लगाने और बातचीत के बाद अनुलग्नक-2 समझौता किया गया था। विशिष्ट अनुबंध "आर. डी. एस. ओ. के ड्राइंग नंबर बी.ए.-10221 (नवीन परिवर्तन यदि कोई हो तो के साथ) के अनुरूप आर. सी. सी. गिट्टी अनुचरों सहित एम. बी. सी. लोडिंग के लिए 6.1 मीटर स्पष्ट अवधि पूर्व-दबाव वाले कंक्रीट पुल स्लैब के निर्माण और परिवहन के लिए था जिसमें मुख्य अभियंता/कॉन/एन. ई. के अधीन निकटतम रेलवे स्टेशन/साइडिंग/रोड पर रेलवे वैगन/रोड वाहन में स्टैकिंग और लोडिंग शामिल है। ई. सी. रेलवे एम. एच. एक्स. अनुलग्नक-5 एक समान अनुबंध है जिसमें पूर्व-दबाव वाले कंक्रीट पुल स्लैब के विनिर्देश को 6,10 मीटर और 5,48 मीटर स्पष्ट अवधि के रूप में दर्शाया गया है जिसमें आर. सी. सी. गिट्टी अनुचरों सहित 25 एम. टी. एमबीजी लोडिंग के साथ है। इसमें अनुबंध में निकटतम रेलवे स्टेशन/साइडिंग आदि पर रेलवे वैगन/लोड वाहन में स्टैकिंग और लोडिंग शामिल है। अनुबंध के अनुसार, माल का निर्माण और परिवहन चालान के बल पर किया जाता था, जिनमें से दो को रिट याचिका

के साथ अनुलग्नक-6 श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुलग्नक-7 विभिन्न बिलों और उनके तहत की गई कटौती का विवरण है जिस पर धनवापसी का दावा किया गया है।

5. विद्वान वकील श्री सत्यबीर भारती ने पंडित इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ; 2011 (2) पी. एल. जे. आर. 444, उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम के. बी. साहा एंड संस इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और अन्य। 9 एस. सी. सी. 97, आयुक्त, दिल्ली मूल्य वर्धित कर बनाम ए. बी. बी. लिमिटेड; (2016) 6 एस. सी. सी. 791 और कोन एलिवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य; (2014) 7 एस. सी. सी. 1 के तर्क करने पर भरोसा किया कि लेन-देन वस्तुओं की शुद्ध और सरल बिक्री थी और वह भी एक अंतर-राज्यीय बिक्री जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा केंद्रीय बिक्री कर (संक्षिप्त "सी. एस. टी". के लिए) का भुगतान किया गया है जिसे उत्तरदाताओं के खिलाफ उठाए गए चालान में जोड़ा गया है।

6. रेलवे की ओर से उपस्थित विद्वान वकील विशेष रूप से प्रत्यर्थी रेलवे की ओर से दायर 26.11.2014 दिनांकित जवाबी हलफनामे का उल्लेख करता है। यह बताया गया है कि अनुबंध दस्तावेज के खंड 34 में विशेष रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर निष्पादित किसी भी कार्य के लिए बिक्री कर के स्रोत पर वसूली की बात की गई है, जिसकी दर भी सकल कार्य मूल्य के 4 प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट की गई है। यह रेलवे का विशिष्ट तर्क है कि काम बिहार के क्षेत्र के भीतर निष्पादित होने के कारण, कटौती केवल उचित थी।

7. हमें पहले अनुलग्नक-2 और अनुलग्नक-5 के रूप में प्रस्तुत समझौतों पर ध्यान देना होगा, जो रेलवे द्वारा विवादित नहीं हैं। इनका सार, विशेष रूप से इसके जवाबी हलफनामे में लिखने तक सीमित है, जो केवल कुछ वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति की

बात करता है। निश्चित रूप से ये बाजार में उपलब्ध वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल में स्थित अपनी विनिर्माण इकाई में रेलवे के विनिर्देशों के अनुसार इसका निर्माण करना होता है और याचिकाकर्ता का दायित्व है कि वह इसके तहत निकटतम रेलवे स्टेशन/साइडिंग/सड़क पर रेलवे वैगन या वाहन में लोड और ढेर करे जो मुख्य अभियंता/कॉन/एन. ई. के अंदर हो। याचिकाकर्ता रेलवे के प्रस्तावित निर्माण पर माल नहीं डालता/नहीं रखता है। यह समझौता वस्तुओं के शुद्ध और सरल निर्माण और बिक्री का है; जो एक कार्य अनुबंध का गठन नहीं करता है। हम यह इस तथ्य के प्रति काफी सचेत कहते हैं कि भले ही कोई कार्य अनुबंध हो, जैसा कि **दिल्ली मूल्य वर्धित कर आयुक्त (उपर्युक्त)** में कहा गया है उस राज्य के भीतर बिक्री के अनुसार अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने का कोई सवाल ही नहीं है जिसमें कार्य अनुबंध किया जाता है, यदि माल की आपूर्ति पूर्व अनुबंध के आधार पर किसी अन्य राज्य से होती है और इसमें कार्य में वृद्धि होती है। **कोन एलिवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ने किसी भी तरह की छूट नहीं दी इस बात पर विवाद के लिए कि कार्य अनुबंध क्या है। माल और श्रम की आपूर्ति के लिए एक समग्र अनुबंध होना चाहिए, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है।

8. वर्तमान मामले में, इस मुद्दे को सरल बनाया गया है क्योंकि बिक्री केवल माल का निर्माण और आपूर्ति है जो माल की बिक्री का एक सरलीकरण है; किन वस्तुओं का परिवहन भी बिक्री के पूर्व अनुबंध के अनुसरण में किया गया है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का कारण है; यहाँ पश्चिम बंगाल राज्य से बिहार राज्य में। राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड; (2002) 5 एस. सी. सी. 203** इस तथ्य प्रस्ताव को दोहराया कि अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री में तीन आवश्यक तत्व होते हैं। एक, माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही के संबंध में, स्पष्ट या निहित शर्त को शामिल करते हुए बिक्री का अनुबंध होना चाहिए। दूसरा, बिक्री के ऐसे अनुबंध के अनुसार माल को

वास्तव में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहिए, बिक्री आवाजाही का निकटतम कारण है और अंत में, ऐसी आवाजाही एक राज्य से दूसरे राज्य में होनी चाहिए जहां बिक्री समाप्त होती है। यह भी माना जाता है कि बिक्री के अनुबंध के बाद स्वतंत्र रूप से होने वाली वस्तुओं की आवाजाही अंतर-राज्यीय बिक्री के अर्थ में नहीं आएगी। इसी तरह, यदि बिक्री का लेन-देन राज्य के भीतर पूरा हो जाता है और उसके बाद माल की आवाजाही होती है, तो यह स्पष्ट रूप से बिक्री के अनुबंध से स्वतंत्रता होगा और आवश्यक रूप से केवल खरीदार द्वारा या उसकी ओर से होगा और इसलिए, लेनदेन में अंतर-राज्य बिक्री तत्व नहीं होगा।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय की एक खंड पीठ ने भी **हैदराबाद अभियांत्रिकी उद्योग बनाम एपी राज्य; (2011) 4 एससीसी 705** में इसी स्थिति की जांच की। इसमें अपीलार्थी, आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर एक पंजीकृत विक्रेता, विद्युत और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण और बिक्री में लगा हुआ था और उन्होंने अपने उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए कंपनी दूसरे कंपनी के साथ एक समझौता किया। अपीलार्थी, दूसरी कंपनी, एजेंट द्वारा जारी बिक्री के आदेशों के अनुसार, उत्पादों को अपने विभिन्न डिपो में ले गया, जहाँ से एजेंट ने सामान एकत्र किया और अंतिम खरीदार को वितरित किया। निर्धारिती-अपीलार्थी ने इसे शाखा हस्तांतरण के रूप में दावा किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया, जिसने इसे सी. एस. टी. अधिनियम के तहत कर के लिए एक अंतर-राज्यीय बिक्री पाया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद पैराग्राफ 39 में इस सिद्धांत को इस प्रकार कहा है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

39. "उपरोक्त निर्णयों से जो सिद्धांत उभरता है वह यह है कि जब बिक्री या बिक्री के लिए समझौता एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का कारण बनता है या

इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे बिक्री के अनुबंध में माल की आवाजाही का प्रावधान किया गया हो या नहीं, या जब किसी शाखा कार्यालय या मुख्य कार्यालय में आदेश दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप माल की आवाजाही होती है, चाहे माल में संपत्ति एक राज्य या दूसरे राज्य में पारित हो, अगर ऐसी बिक्री का प्रभाव एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही पर पड़ता है, तो एक अंतर-राज्यीय बिक्री होगी और इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत ऐसे लेनदेन के कारोबार पर कर की अनिवार्यता होगी। यह केवल तभी होगा जब अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद से संबंधित कारोबार केंद्रीय अधिनियम के तहत कर योग्य होगा।

10. वर्तमान मामले में भी एक अनुबंध के लिए सटीक और विशेष विनिर्देशन के पूर्व-दबाव वाले कंक्रीट स्लैब और आर. सी. सी. बैलास्ट रिटेनर्स का निर्माण और परिवहन है। इसमें कोई कार्य अनुबंध शामिल नहीं है और यह केवल याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित वस्तुओं की शुद्ध और सरल बिक्री है, जिसे अनुबंध दिया गया है; जो केवल निर्माण और बिक्री के लिए है। निर्मित वस्तुओं को एक वाहन या रेलवे वैगन में लादा और रखा जाता है, जिसके द्वारा इसे रेलवे के कार्यों में वृद्धि के लिए बिहार राज्य के भीतर साइट पर ले जाया जाता है; जो काम या वृद्धि याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है। लेन-देन विशुद्ध रूप से वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री का है और न तो एक कार्य अनुबंध है और न ही बिहार राज्य के भीतर कर के लिए अपेक्षित वस्तुओं की बिक्री है जो अनुलग्नक-2 और अनुलग्नक-5 समझौतों के अनुसार वस्तुओं की बिक्री एक अंतर-राज्यीय बिक्री है जो बिहार राज्य के भीतर कर के लिए उपयुक्त नहीं है।

11. रेलवे ने इस आधार पर कटौती की थी कि यह एक कार्य अनुबंध है जिसे हमने अस्वीकार कर दिया है। रेलवे याचिकाकर्ता ठेकेदार को बिलों से की गई अवैध कर कटौती

वापस करने के लिए बाध्य है।रेलवे निश्चित रूप से बिहार मूल्य वर्धित कर विभाग से रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है।

12. इस संदर्भ में, हमें पंडित इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड पर ध्यान देना होगा कि रेलवे ने इसी तरह के लेन-देन को अंतर-राज्यीय लेन-देन में अवैध रूप से कटौती माना गया था।

13. रेलवे के विद्वान स्थायी वकील ने बताया कि समझौते में एक मध्यस्थता खंड है और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अनुच्छेद 226 के तहत लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से एक संविदात्मक मामले में।

14. हमें नहीं लगता कि जो विवाद उठाया गया था वह मध्यस्थता योग्य था, विशेष रूप से क्योंकि इसमें इस बात पर विचार करना शामिल था कि क्या लेन-देन बिहार राज्य के भीतर वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री, कार्य अनुबंध या बिक्री थी।

15. उपरोक्त परिस्थितियों में हम धनवापसी का निर्देश देते हैं, लेकिन, उपरोक्त रिट याचिका के पंजीकरण की तारीख से तीन साल पहले की गई कटौती तक सीमित है जो 14.05.2012 पर है; सीमा अधिनियम के तहत धन की वसूली के लिए निर्धारित सीमा को प्रभावी बनाता है। रेलवे इस फैसले की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि वापस करेगा। यदि उस समय के भीतर धनवापसी नहीं दी जाती है तो ब्याज 4 महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 प्रतिशत की दर से चलेगा। रेलवे बिहार राज्य से धनवापसी या भविष्य के बकाया के समायोजन के लिए आवेदन कर सकता है।

16. रिट याचिका की उपरोक्त अनुमति के साथ दी गई है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायाधीश)